

आप्त समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 16 अंक : 37

लखनऊ, बुधवार 07 जनवरी 2026 सऽ13 जनवरी 2026 तक

पृष्ठ—8

मूल्य : एक रुपया

सेमीकंडक्टर निवेश को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन, पीलीभीत से वाराणसी तक विकास योजनाओं पर कैबिनेट की मुहर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने वाले कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार की जनवरी 2024 में लागू सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से ₹3,000 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 94 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 93 को स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमीकंडक्टर निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है और अब उत्तर प्रदेश को इस उभरते उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में योगी सरकार ने केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सेमीकंडक्टर इकाइयों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत की प्रतिपूर्ति, 90 वर्षों तक नेट एसजीएसटी में छूट, उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 900 प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति (अधिकतम ₹ 2,000 प्रतिमाह), जल मूल्य में छूट तथा 90 वर्षों तक प्रति यूनिट ₹ 2 बिजली दर में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करना है। कैबिनेट बैठक में पीलीभीत के टनकपुर रोड स्थित मुख्यालय के पास एक आधुनिक

बस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह बस स्टेशन राजस्व विभाग की 9.397 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाएगा, जिसे आगे 60 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। इस बस स्टेशन के निर्माण से उत्तराखंड और नेपाल जाने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य



दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कैबिनेट ने शिव प्रसाद गुप्ता एसएसपीजी मंडलीय जिला चिकित्सालय, वाराणसी परिसर में स्थित 99 जर्जर एवं अनुपयोगी भवनों को 6 वस्त कर 500 शैय्या वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। यह अस्पताल 395 करोड़ 88 लाख रुपये की लागत से बनेगा, जिसका निर्माण कार्य चार वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। परियोजना की 60 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इससे पूर्वांचल क्षेत्र के मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कैबिनेट ने खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन को स्वीति दी है। विभाग में कुल 96 पद स्वीकृत हैं। अब दो-तिहाई पद पदोन्नति के माध

सामाजिक नाटक 'ब्लैक होल' का मंचन आठ को



लखनऊ। सामाजिक नाटक 'ब्लैक होल' का मंचन आठ जनवरी को राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह कैसरबाग में होगा। वर्तमान संदर्भों को रेखांकित करता यह नाटक रामकिशोर नाग का लिखा हुआ है। गत वर्ष अक्टूबर में हास्य नाटक 'हम तो चले हरिद्वार' के बाद संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के सहयोग से बिम्ब सांस्कृतिक समिति के कलाकार महर्षि कपूर के निर्देशन में बुधवार शाम सात बजे आत्मकेंद्रित संस्कृति और मानवीयता के बदलते जा रहे मानदंडों को नाटक प्रस्तुत करेंगे।

यम से और एक-तिहाई पद अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों (ओलंपिक, एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स) से भरे जाएंगे। इस निर्णय से अनुभवी अधिकारियों के साथ-साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने कानपुर स्थित 39वीं वाहिनी पीएसी के पुराने एवं जर्जर आवासीय भवनों को ध्वस्त करने और उनके स्थान पर टाइप-वन स्पेशल के 90 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे पीएसी जवानों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर (गुजरात) के वाराणसी में ऑफ-कैंपस की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह भूमि तहसील राजा तालाब क्षेत्र में स्थित है, जिसे पशुधन विभाग से 66 वर्षों की लीज पर विश्वविद्यालय को दी जाएगी। इस कैंपस की स्थापना से फॉरेंसिक साइंस, साइबर अपराध और आपराधिक जांच के क्षेत्र में प्रदेश को शैक्षणिक और तकनीकी मजबूती मिलेगी।

जयशंकर की फ्रांस यात्रा, रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर फोकस

नई दिल्ली/पेरिस। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर फ्रांस के आधिकारिक दौरे पर हैं, जो भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी में लगातार बनी गति को दर्शाता है। पेरिस पहुंचे डॉ. जयशंकर अपनी इस यात्रा के दौरान फ्रेंच राजदूतों के सम्मेलन के 39वें एडिशन को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर संबोधित करेंगे, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी की गहराई और परिपक्वता को दिखाता है। अपनी यात्रा

के पहले दिन, डॉ. जयशंकर ने पेरिस में 'भारत और फ्रांस के बीच बुनी हुई कहानियां' नाम की एक प्रदर्शनी देखी। एक्स पर एक पोस्ट में अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए विदेश मंत्री ने लिखा आज शाम पेरिस में 'भारत और फ्रांस के बीच बुनी हुई कहानियां' प्रदर्शनी देखी। यह प्रदर्शनी भारत की टेक्सटाइल विरासत जानकारी

परीक्षा पर चर्चा 2026' को लेकर शिक्षा विभाग सक्रिय, कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों का होगा ऑनलाइन पंजीकरण

लखनऊ। प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित किए जाने वाले 'परीक्षा पर चर्चा 2026' कार्यक्रम को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए



गए हैं। जारी पत्र के अनुसार, परीक्षा पर चर्चा का 6वां संस्करण जनवरी 2026 में प्रस्तावित है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के छात्र-छात्राएं, शिक्षक एवं अभिभावक भाग ले सकेंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 9 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण एवं चयन प्रक्रिया के तहत <https://innovateindia1-mygov-in/> पोर्टल पर एक ऑनलाइन बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) प्रतियोगिता आयोजित की

जा रही है। चयनित प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत विद्यालयों में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए बैनर, पोस्टर, इन्फोग्राफिक्स एवं क्यूआर कोड का उपयोग किया जाएगा। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #PPC2026 हैशटैग के माध्यम से प्रचार करने और विद्यालय स्तर पर स्वयं के पोस्टर, वीडियो व क्रिएटिव सामग्री साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्थानीय एफएम चौनलों, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा यूट्यूब चौनलों के माध्यम से भी कार्यक्रम का प्रचार सुनिश्चित करने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए, ताकि 'परीक्षा पर चर्चा 2026' कार्यक्रम को सफल बनाया जा सके।

और रचनात्मकता को दिखाती है। यह भारत-फ्रांस के मजबूत सांस्कृतिक जुड़ाव की भी याद दिलाती है। इसके बाद 5 जनवरी को डॉ. जयशंकर ने फ्रेंच-इंडियन यंग



टैलेंट्स प्रोग्राम के प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। यह पहल चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फ्रांस-इंडिया द्वारा आयोजित की गई थी। बातचीत में वैश्विक बदलावों और उभरती चुनौतियों से निपटने में भारत-फ्रांस सहयोग की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बातचीत के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने एक्स

पर लिखा दुनिया में हो रहे बदलावों और उस संदर्भ में भारत-फ्रांस सहयोग के महत्व पर चर्चा की। उसी दिन बाद में विदेश मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक, फितोह बिरोल से मुलाकात की। बैठक के बाद, डॉ. जयशंकर ने एक्स पर लिखा आज सुबह अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फितोह बिरोल से मुलाकात की। वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य के उनके आकलन और भारत की वृद्धि और विकास के लिए उनके समर्थन की सराहना करता हूँ। विदेश मंत्री फ्रांस की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद लकजमबर्ग भी जाएंगे, जहां वे लकजमबर्ग के ग्रैंड डची के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेट्टेल के अलावा अन्य वरिष्ठ नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों व विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

सम्पादकीय

चुनावी तोहफे और बढ़ती देनदारियाँ

चुनाव नजदीक आते ही राज्यों में लोकलुभावन घोषणाओं की बाढ़ आना अब सामान्य राजनीतिक प्रवृत्ति बन चुकी है। असम और तमिलनाडु की हालिया घोषणाएँ इसी सिलसिले की अगली कड़ी हैं, जहाँ तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व खड़े किए जा रहे हैं। असम सरकार ने विध



मानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना की घोषणा की है, जिसके तहत ३७ लाख महिलाओं के खातों में ८,००० रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य भले ही महिला सशक्तिकरण बताया जा रहा हो, लेकिन इससे राज्य के खजाने पर लगभग ३०,००० करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सवाल यह है कि क्या राज्य की वित्तीय स्थिति इस भार को लंबे समय तक वहन करने में सक्षम है? उधर, तमिलनाडु में अगले वर्ष होने वाले विधमानसभा चुनावों से पहले सरकार ने अपने कर्मचारियों को साधने की दिशा में बड़ा दांव खेला है। तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अंतिम वेतन का कम से कम ५० प्रतिशत पेंशन देने और २५ लाख रुपये तक ग्रेज्युटी सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया है। इसके लिए कर्मचारियों का योगदान केवल १० प्रतिशत होगा, जबकि शेष पूरा बोझ राज्य सरकार उठाएगी। फिलहाल इससे १३,००० करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च अनुमानित है, जो महंगाई के साथ हर साल बढ़ता जाएगा। बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना एक आवश्यक और मानवीय नीति है, लेकिन यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारियों तक सीमित क्यों हो? देश की बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जहाँ न पेंशन है और न सामाजिक सुरक्षा। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को एक अलग, सुविधा-प्राप्त वर्ग के रूप में स्थापित करना सामाजिक असमानता को और गहरा करता है। नई पेंशन व्यवस्था इसी असमानता और बढ़ते वित्तीय दबाव को ध्यान में रखकर लागू की गई थी। अब चुनावी लाभ के लिए उसे पलटना न केवल नीति की निरंतरता को तोड़ता है, बल्कि भविष्य की सरकारों के लिए गंभीर आर्थिक चुनौतियाँ भी खड़ी करता है। बेहतर होता कि सरकारें चुनावी वादों की बजाय एक ऐसी व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति पर काम करतीं, जो समाज के सभी वर्गों को न्यूनतम सुरक्षा प्रदान करे। लोकतंत्र में कल्याण आवश्यक है, लेकिन वह दूरदर्शिता और समानता के साथ होना चाहिए न कि केवल वोट बैंक को ध्यान में रखकर।

डिजिटल हाउस अरेस्ट के नाम पर ५४ लाख की साइबर ठगी, चार आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ। साइबर अपराधियों ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी राजेंद्र प्रकाश वर्मा को "डिजिटल हाउस अरेस्ट" का डर दिखाकर ५४ लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को एटीएस और एनआईए का अधिकारी बताते हुए वीडियो कल के माध्यम से वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने गिरफ्तारी का भय दिखाकर पीड़ित को कथित तौर पर डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखा और अलग-अलग खातों में ५४ लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। मामले की जांच के बाद साइबर क्राइम टीम ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपी उजैर खान लखनऊ में नीट (NEET) की कोचिंग कर रहा था, जबकि ठगी की रकम थाईलैंड में बैठे मास्टरमाइंड तक पहुंचाई जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर करने के बदले मोटा कमीशन लेते थे। साइबर क्राइम टीम अब गिरोह के विदेशी नेटवर्क और मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात वीडियो कॉल, खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताने वाले फोन कॉल या डिजिटल हाउस अरेस्ट जैसे दावों से सतर्क रहें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।

जेएस विश्वविद्यालय का परिसमापन, आईआईएमटी विश्वविद्यालय के ग्रेटर नोएडा ऑफ-कैंपस को मंजूरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े दो महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाले प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। एक तरफ, योगी कैबिनेट ने जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद (जनपद फिरोजाबाद) के परिसमापन को मंजूरी दी है तो वहीं आईआईएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ के ग्रेटर नोएडा में ऑफ-कैंपस को संचालन प्राधिकार पत्र (एलओपी) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद के परिसमापन के प्रस्ताव की मंजूरी के निर्णय की जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि जांच में यह सामने आया कि विश्वविद्यालय द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए बीपीएड पाठ्यक्रम की फर्जी और बैंक डेट में मार्कशीट व डिग्रियां जारी की गईं, जिनका उपयोग राजस्थान की शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती परीक्षा-२०२२ में चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किया गया। इस प्रकरण में राजस्थान पुलिस की जांच, कुलाधिपति एवं कुलसचिव की गिरफ्तारी तथा शासन स्तर पर गठित जांच समितियों की आख्या में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। मंत्री ने बताया कि जेएस विश्वविद्यालय द्वारा अधिनियम की

विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया गया है, जिसमें डिग्री प्रदान करने की शक्ति का दुरुपयोग, संगठित अपराध के रूप में फर्जी अंकतालिकाओं एवं डिग्रियों का वितरण, आवश्यक भूमि मानक का पालन न करना तथा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को अनिवार्य विवरण उपलब्ध न कराना शामिल है। इन सभी तथ्यों के



दृष्टिगत योगी सरकार ने जेएस विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद के परिसमापन का निर्णय लिया है। परिसमापन के पश्चात विश्वविद्यालय के समस्त अभिलेख डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के संरक्षण में रखे जाएंगे तथा उन्हीं अभिलेखों के आधार पर पूर्व में निर्गत मार्कशीट एवं डिग्रियों का प्रमाणीकरण किया जाएगा। साथ ही, परिसमापन अवधि के दौरान विश्वविद्यालय की गतिविधियों के संचालन हेतु धारा ५५(६) के अंतर्गत त्रि-सदस्यीय अंतरिम समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक में दूसरा अहम निर्णय आईआईएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ के ग्रेटर नोएडा में ऑफ-कैंपस की

स्थापना को लेकर लिया गया। इसके लिए संचालन प्राधिकार पत्र (एलओपी) जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस ऑफ-कैंपस के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र में उच्च शिक्षा के नए अवसर सृजित होंगे और छात्रों को अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ तथा उसके द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०२१ के अंतर्गत परिसर दूरस्थ केंद्र की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस क्रम में प्रायोजक संस्था एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, मेरठ द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ४.७६६ एकड़ भूमि चिन्हित की गई थी, जिसके लिए २५ फरवरी २०२५ को आशय पत्र (एलओआई) निर्गत किया गया था। अब सरकार द्वारा आईआईएमटी विश्वविद्यालय, मेरठ के ग्रेटर नोएडा स्थित ऑफ-कैंपस के संचालन हेतु प्रायोजक संस्था को संचालन प्राधिकार पत्र (एलओपी) जारी करने के प्रस्ताव को स्वीति दी गई है। मंत्री ने कहा कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं एनसीआर क्षेत्र में उच्च शिक्षा के अवसरों का विस्तार होगा और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

दिसंबर में यूपी का राजस्व बढ़ा, पिछले वर्ष से १०७४ करोड़ रुपये अधिक प्राप्ति: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि प्रदेश के प्रमुख कर एवं करेक्टर राजस्व मदों से वित्तीय वर्ष २०२५ २६ के दिसंबर माह में कुल १८,६७६.३८ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि वित्तीय वर्ष २०२४ २५ के दिसंबर माह में यह आंकड़ा १७,६०५.३२ करोड़ रुपये रहा था। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में दिसंबर माह में १,०७४.०६ करोड़ रुपये की अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति दर्ज की गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि कर राजस्व मदों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०२५ २६ में दिसंबर माह तक कुल १,५६,७३०.८८ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो इस अवधि तक निर्धारित लक्ष्य का ७४.२ प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से मांग में वृद्धि हुई है, जिसका सकारात्मक प्रभाव राजस्व संग्रह पर पड़ा है। आने वाले समय में राजस्व प्राप्ति और बेहतर होने की संभावना है। श्री खन्ना ने बताया कि जीएसटी के अंतर्गत दिसंबर २०२५ में ६,५६३.०४ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि दिसंबर २०२४ में यह ६,३४२.६८ करोड़ रुपये था। वैट के अंतर्गत दिसंबर २०२५ में ३,०८६.८३

करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी माह में ३,१०५.६१ करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डीजल और पेट्रोल पर कर अन्य राज्यों की तुलना में कम है तथा इलेक्ट्रिक वाहनों और एथेन ल के बढ़ते प्रयोग से ईंधन की खपत में कमी आई है। आबकारी मद में दिसंबर २०२५ के



दौरान ४,६८२.८४ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जबकि दिसंबर २०२४ में यह ४,१४१.७५ करोड़ रुपये था। स्टाम्प एवं निबंधन मद से दिसंबर २०२५ में २,६६५.५६ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, जबकि पिछले वर्ष इसी माह में २,७८४.६६ करोड़ रुपये का राजस्व मिला था। परिवहन मद में दिसंबर २०२५ की प्राप्ति ६०६.५७ करोड़ रुपये रही, जबकि दिसंबर २०२४ में यह ६०५.८४ करोड़ रुपये थी। करेक्टर राजस्व की प्रमुख मद भू-तत्व एवं खनिकर्म के अंतर्गत

दिसंबर २०२५ में ४४१.५१ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, जबकि दिसंबर २०२४ में यह ४२४.१८ करोड़ रुपये थी। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष २०२५ २६ में दिसंबर माह तक मुख्य कर राजस्व के अंतर्गत कुल १,५६,७३०.८८ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो निर्धारित लक्ष्य २,१५,३५८.६५ करोड़ रुपये के सापेक्ष ७४.२ प्रतिशत है। राज्यकर मद में दिसंबर तक १,३०,०५३.५५ करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष ८४,०६०.६६ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो लक्ष्य का ६४.६ प्रतिशत है। आबकारी मद में ४३,४०० करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष ३६,८२६.६८ करोड़ रुपये (६१.८ प्रतिशत), स्टाम्प एवं निबंधन मद में २८,५२५ करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष २४,३८६.०६ करोड़ रुपये (८५.५ प्रतिशत) तथा परिवहन मद में १०,०६२.६० करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष ८,८४४.०१ करोड़ रुपये (८७.६ प्रतिशत) की प्राप्ति दर्ज की गई है। इसके अलावा भू-तत्व एवं खनिकर्म मद में दिसंबर तक ४,२०० करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले २,८१७.८३ करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है, जो लक्ष्य का ६७.१ प्रतिशत है।

कैबिनेट के अहम फैसले: पारिवारिक दान विलेखों पर स्टाम्प शुल्क में छूट, जीसीसी नीति की नियमावली को मंजूरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-२०२४ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमावली-२०२५ को मंजूरी प्रदान की गई। इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश को वैश्विक निवेश, उच्च स्तरीय सेवाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में नई गति मिलेगी। कैबिनेट से अनुमोदित नियमावली के अंतर्गत इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह नियमावली जीसीसी नीति-२०२४ के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी तथा राज्य सरकार द्वारा संशोधन अथवा समाप्त किए जाने तक लागू रहेगी। यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कैबिनेट के निर्णय के विषय में बताया कि प्रदेश में निवेश का माहौल बेहतर हुआ है, जिसके चलते निवेश करने के लिए उद्योग घराने और मल्टीनेशनल कंपनियों हमारे संपर्क में हैं। जीसीसी नीति हमारे लिए बहुत लाभप्रद है और आज हम इसकी एसओपी लेकर आए हैं। यूपी में जीसीसी के निवेश में लगातार वृद्धि हो रही है। चालू

वित्तीय वर्ष में २१ कंपनियों ने इसमें निवेश प्रारंभ कर दिया है। इसके माध्यम से प्रदेश में व्यापक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नियमावली के अनुसार, जीसीसी किसी भारतीय अथवा विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित एक कैप्टिव इकाई होगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास



(आरएंडडी), वित्त, मानव संसाधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और नॉलेज सर्विसेज जैसे रणनीतिक कार्यों का निष्पादन करेगी। इस नियमावली में जीसीसी इकाइयों को आकर्षित करने के लिए कई प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। इनमें फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी, स्टॉप ड्यूटी में छूट अथवा प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, संचालन व्यय (ओपेक्स) सब्सिडी, पेट्रोल और भर्ती सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, प्रतिभा विकास एवं कौशल प्रोत्साहन, अनुसंधान एवं नवाचार

प्रोत्साहन के साथ-साथ केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन शामिल हैं। वित्तीय लाभ के अतिरिक्त, जीसीसी इकाइयों को तकनीकी सहायता समूह, इंडस्ट्री लिंकेज सपोर्ट, विनियामक सहायता, आवेदन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण, अनुमोदन एवं प्रोत्साहन वितरण की सुव्यवस्थित प्रक्रिया भी उपलब्ध कराई जाएगी। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत मिलने वाले सभी प्रोत्साहन, भारत सरकार की किसी भी योजना अथवा नीति के तहत उपलब्ध लाभों के अतिरिक्त होंगे। किसी भी विधिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल लखनऊ स्थित न्यायालयों का होगा। स्वीत प्रोत्साहन राशि का वितरण वित्त विभाग के प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय को प्रदेश को ग्लोबल सर्विस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जीसीसी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में उच्च कौशल आधारित निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

सभी गांवों में 30 जनवरी तक खुल जाएगी डिजिटल लाइब्रेरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत अब सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को बड़े-बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार ३० जनवरी



तक सभी जिलों में आईटी उपकरणों की खरीद पूरी कर ग्राम पंचायत सचिवालयों में अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की तैयारी में जुटी है। यह पहल ग्रामीण प्रतिभाओं को देश के बड़े कोचिंग और अध्ययन केंद्रों जैसी सुविधाएं उनके अपने गांव में उपलब्ध कराने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। २६ जनवरी तक पुस्तकालयों के लिए फर्नीचर की खरीद पूरी कर लेने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद डिजिटल लाइब्रेरी संचालन के लिए तैयार होंगी। पंचायतीराज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी में वाईफाई, एलईडी स्क्रीन, सीसीटीवी

कैमरे, कंप्यूटर सिस्टम के साथ-साथ किताबों और डिजिटल कंटेंट की समृद्ध व्यवस्था होगी। ई-बुक्स, वीडियो और अडियो लेक्चर, विवज और लाखों डिजिटल शैक्षणिक सामग्री के जरिए ग्रामीण युवा अब अपने गांव में रहकर ही उच्च स्तरीय तैयारी कर सकेंगे। हर जिले की ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। प्रत्येक लाइब्रेरी पर करीब ४ लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें २ लाख रुपए की पुस्तकें, १.३० लाख रुपए के आईटी उपकरण और ७० हजार रुपए के आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। योगी सरकार की यह पहल ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और विकसित भारत की दिशा में युवाओं को बराबरी का अवसर देने वाला मजबूत कदम मानी जा रही है। पंचायतीराज निदेशक ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव लाइब्रेरी का प्रबंधन करेंगे, जबकि सहायक अधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर मजबूत होगा और युवा रोजगार व प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक सक्षम बनेंगे।

उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी, दो करोड़ ४९ लाख नाम कटे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में लगभग हर पांचवें वोटर का नाम स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR) के बाद हटाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन अफ इंडिया (ECI) ने मंगलवार को ड्राफ्ट रोल जारी किया, जिसमें २.८६ मिलियन लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। यह उन बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा प्रतिशत है जहां यह विवादित प्रक्रिया चलाई गई है। यह आंकड़ा पूर्व की संख्या १५.४४ करोड़ से लगभग दो करोड़ ८६ लाख कम है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गयी है। इसमें १२ करोड़ ५५ लाख ५६ हजार २५ मतदाता शामिल हैं। पिछले साल २७ अक्टूबर की मतदाता सूची में १५ करोड़ ४४ लाख ३० हजार ६२ मतदाता थे। मसौदा सूची में लगभग २.८६ करोड़ मतदाताओं को गिनती के दौरान शामिल नहीं किया जा सका है। सीईओ ने कहा कि अब मसौदा मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां छह जनवरी से छह फरवरी तक दर्ज करायी जा सकेंगी। इस दौरान लोग सूची में नाम शामिल करने, सुधार करने या आपत्ति करने के लिए आवेदन कर

सकते हैं। रिणवा ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि ४६.२३ लाख मतदाता (२.६६ प्रतिशत) मृत पाए गए, जबकि २.५७ करोड़ मतदाता (१४.०६ प्रतिशत) या तो स्थायी रूप से बाहर चले गये थे या प्रमाणन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद नहीं थे। वहीं, २५.४७ लाख अन्य मतदाताओं का नाम एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाया गया। उन्होंने कहा, मसौदा मतदाता सूची में अब १२.५५ करोड़ मतदाता हैं और इसमें राज्य के सभी ७५ जिले और ४०३ विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। रिणवा ने बताया कि इस काम में एक लाख ७२ हजार ४८६ बूथ शामिल किये गये थे। इनमें बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) फार्म भरवाने के लिये मतदाताओं तक पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त ५,७६,६११ बूथ स्तरीय एजेंटों ने भी इस काम में मदद की। सीईओ ने बताया कि प्रदेश में एसआईआर की कवायद मूल रूप से ११ दिसंबर को खत्म होने वाली थी लेकिन लगभग दो करोड़ ६७ लाख मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से बाहर हो रहे थे जिसके बाद १५ दिन का अतिरिक्त समय मांगा गया। इसके मद्देनजर निर्वाचन आयोग की मंजूरी से एसआईआर प्रक्रिया की अवधि २६ दिसंबर तक बढ़ा दी

गयी थी। रिणवा ने बताया कि शुरू में मसौदा मतदाता सूची जारी करने की तारीख ३१ दिसंबर तय की गई थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से बाद में इसे छह जनवरी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के मसौदा तैयार करने के बाद उसकी आलोचना की है। उप्र कांग्रेस अध



यक्ष अजय राय ने 'पीटीआई वीडियो' से बात करते हुए कहा कि मतदाता सूची तैयार करने के लिए आवंटित समय बहुत कम था। उन्होंने कहा, "यह पूरी तरह से जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में केवल एक महीने का समय देकर एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने का तरीका अनुचित है।" राय ने कहा, "उन्होंने (निर्वाचन आयोग ने) केरल जैसे छोटे राज्य को भी एक महीने का समय दिया। उत्तर प्रदेश को कम से कम पांच से छह महीने का समय दिया जाना चाहिए था, जैसा कि २००२-०३ में किया गया था... अगर ऐसा किया गया होता, तो

बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) पर इतना दबाव नहीं होता और आत्महत्याओं को रोका जा सकता था।" समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव के लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में मतदाता सूची के मसौदे को लेकर निर्वाचन आयोग को चेतावनी दी। कन्नौज के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 'एक्स' पर कहा, "मतदाताओं के गुस्से के आंदोलन में बदलने से पहले, निर्वाचन आयोग को मैनपुरी में एसआईआर से हटाए गए वैध नामों का संज्ञान लेते हुए मतदाता सूची को सही करना चाहिए।" कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्ल ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर की मसौदा सूची जारी होने के बाद मंगलवार को दावा किया कि उनका और उनके परिवार के सदस्यों के

नाम एसआईआर से गायब हैं, जबकि उनके पास सारे कागजात हैं तथा २००३ की मतदाता सूची में भी उनके नाम थे। कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य ने कहा कि उनका नाम सिर्फ इस आधार पर काट दिया गया कि उन्होंने अपना नाम साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से नोएडा विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित कराया था। इस बीच आयोग ने छह जनवरी से छह फरवरी तक आपत्ति और दावे प्रस्तुत करने के लिए एक विंडो खोली है, जिसके दौरान कोई भी पात्र मतदाता जिसका नाम दर्ज नहीं है, फॉर्म-६ जमा करके अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकता है। एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए मतदाताओं के नाम जांच के बाद केवल एक सत्यापित स्थान पर ही दर्ज रखे जाएंगे।

ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार दो लोगों की मौत

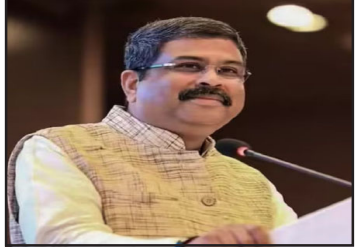
अमेठी। जिले में मंगलवार देर शाम ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, मृतकों की पहचान मोनू यादव (२८) और दिग्विजय सिंह (५०) के रूप में हुई है। इस हादसे में शिवनाथ (३०) गंभीर रूप से घायल हो गया,

जिसे सीएचसी अमेठी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसा अमेठी-प्रतापगढ़ मार्ग के बाईपास मोड़ पर मां कालिका ढाबा के पास हुआ। अमेठी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) रवि सिंह ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

भारतीय भाषाओं को मिली नई पहचान: शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ५५ विद्वत ग्रंथों का किया विमोचन

लखनऊ। भारत की भाषायी विरासत को मजबूत करने और शास्त्रीय भाषाओं को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की दिशा में आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ५५ विद्वत ग्रंथों का विमोचन किया, जो राष्ट्र की बौद्धिक चेतना के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो रहा है। यह कार्यक्रम भारतीय भाषाओं को शिक्षा, अनुसंधान और सांस्कृतिक स्वाभिमान के केंद्र में स्थापित करने का प्रतीक बन गया। इन ग्रंथों को कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ओड़िया, तमिल एवं भारतीय सांकेतिक भाषा में तैयार किया गया है। इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा, साहित्य, दर्शन और भाषायी विकास जैसे गहन विषय शामिल हैं। विशेष रूप से तमिल महाकाव्य शतरुक्कुरलश का सांकेतिक भाषा में भावार्थ प्रस्तुत करना सराहनीय रहा, जो समावेशी भारत की दृष्टि को साकार करता है। इससे

दिव्यांगजन समुदाय तक ज्ञान की पहुँच सुनिश्चित हुई, जो समाज के हर वर्ग को जोड़ने वाली पहल है। शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने विमोचन अवसर पर कहा कि यह केवल साहित्यिक प्रयास नहीं, बल्कि भारत की आत्मा को सहेजने का संकल्प है। उन्होंने जोर दिया कि भारतीय भाषाएँ संवाद का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि बौद्धिक समृद्धि की कुंजी हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अनुरूप यह कदम मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देगा, जिससे नई पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़कर अधिक रचनात्मक बनेगी। औपनिवेशिक मैक ले सोच के विपरीत, आज का



भारत भाषाओं को एकता का सेतु मानता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, 'भारत की सभी भाषाएँ राष्ट्रभाषाएँ हैं।' यह कथन लोकतांत्रिक भारत की विविधता में एकता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। कार्यक्रम में भारत को विविधता का जीवंत उदाहरण बताया गया, जहाँ भाषाएँ कभी बाधा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक समरसता का आधार रहीं। इस प्रयास में भारतीय भाषा समिति, सेंटर अ फ एक्सिलेंस, सेंट्रल इंस्टीट्यूट अ फ इंडियन लैंग्वेज (CIIL) और सेंट्रल इंस्टीट्यूट अ फ क्लासिकल तमिल (CICT) की महत्वपूर्ण भूमिका रही। शिक्षा मंत्री ने इन संस्थानों को बधाई दी और भविष्य में ऐसे निरंतर प्रयासों का आह्वान किया। यह विमोचन भारतीय वाङ्मय में मूल्यवान योगदान है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर तीन साल की राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती-२०२५ के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस

संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सीधी भर्ती-२०२५ के अंतर्गत कुल ३२,६७६ पदों को भरे जाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके मुताबिक आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष महिला), आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर

(पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह



आयु छूट एक बार के लिए प्रदान की जाएगी। सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के

शीतलहर और घने कोहरे के चलते लखनऊ में कक्षा ८ तक स्कूल बंद, ९ से १२वीं की कक्षाएं सीमित समय में संचालित

लखनऊ। शीतलहर एवं घने कोहरे की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा जारी आदेश के अनुसार जनपद लखनऊ में कक्षा प्री-प्राइमरी से कक्षा ८ तक संचालित समस्त परिषदीय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों सहित सभी बोर्डों से संबद्ध विद्यालयों में ८ जनवरी २०२६ तक अवकाश घोषित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं कक्षा ९ से कक्षा १२ तक की कक्षाएं परिवर्तित समय-सारिणी के अनुसार प्रातः १०:०० बजे से अपराह्न ३:०० बजे तक संचालित

की जाएंगी। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश की प्रामाणिकता जनपद की आधि



कारिक वेबसाइट <https://lucknow-nic.in> पर सत्यापित की जा सकती है। जिला सूचना अधिकारी को आदेश की प्रति जनपद की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर प्रदर्शित कराने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि उप निदेशक सूचना को समाचार पत्रों एवं मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश के अनुपालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन के इस निर्णय से अभिभावकों और विद्यार्थियों को ठंड और कोहरे से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अमृत 2.0 योजनान्तर्गत 16वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक सम्पन्न

लखनऊ:। मुख्य सचिव श्री एस.पी. गोयल की अध्यक्षता में अमृत 2.0 योजनान्तर्गत १६वीं राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुल १८.६१७२.२२ लाख रुपये की अनुमानित लागत वाली ३३ पेयजल परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया। इनमें ट्रेच-१ की ४२७४६.०६ लाख रुपये अनुमानित लागत वाली ०५ परियोजनाएं, ट्रेच-२ की ६२३२६.३७ लाख रुपये अनुमानित लागत वाली ११ परियोजनाएं तथा ट्रेच-३ की ८.९०६३.७६ लाख रुपये अनुमानित लागत वाली १७ परियोजनाएं शामिल हैं। इन अनुमोदित परियोजनाओं के माध्यम से २.८७.८०१ गृह संयोजन प्रदान करने हेतु नए नलकूपों का निर्माण, रिबोर नलकूपों का कार्य, पूर्व निर्मित उच्च जलाशयों की मरम्मत, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पंप हाउस तथा संबंधित कार्य कराए जाएंगे। ट्रेच-१ के अंतर्गत बुलन्दशहर की स्याना नगर पालिका परिषद पेयजल संतृप्तीकरण योजना, कुशीनगर की रामकोल

नगर पंचायत पेयजल विस्तार एवं सु ढीकरण योजना, वाराणसी नगर निगम के १८ अत्यधिक प्रभावित वार्ड क्लस्टर-१ (हुकुलगंज एवं नई बस्ती वार्ड) में पेयजल विस्तारीकरण योजना तथा

योजना सम्मिलित हैं। ट्रेच-२ के अंतर्गत वाराणसी नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र में ट्रान्स वरुणा जलापूर्ति योजना लमही जोन, वाराणसी नगर निगम के १८ अत्यधिक प्रभावित वार्ड क्लस्टर-५



वाराणसी नगर निगम के १८ अत्यधिक प्रभावित वार्ड क्लस्टर-४ (दुर्गाकुण्ड, नरिया, सरायनंदन, जोल्हा उत्तरी एवं भेलूपुर वार्ड), वाराणसी नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र में ट्रान्स वरुणा जलापूर्ति योजना लमही जोन (फेज-१, पार्ट-बी) में पेयजल विस्तारीकरण

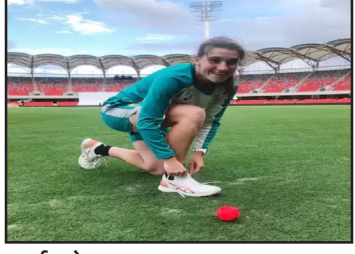
(शिवाला, नगवां, बाघाड़ा, जंगमबाड़ी एवं बंगाली टोला वार्ड) में पेयजल विस्तारीकरण योजना, एटा में जलेसर नगर पालिका परिषद में पुनर्गठन पेयजल योजना, प्रतापगढ़ में रानीगंज नगर पंचायत में पुनर्गठन पेयजल योजना, महोबा में कबरई नगर पंचायत पेयजल योजना,

मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद पेयजल पुनर्गठन योजना जोन-१, २, ३, ४ एवं ५ पार्ट-१, आगरा में फतेहाबाद नगर पंचायत पेयजल योजना, सहारनपुर में बेहट नगर पंचायत में पेयजल संवर्धन एवं सु ढीकरण योजना, सहारनपुर में तीतरों नगर पंचायत में पेयजल संवर्धन एवं सु ढीकरण योजना, नानौता नगर पंचायत में पेयजल संवर्धन एवं सु ढीकरण योजना तथा गोरखपुर में नगर निगम गोरखपुर पुनर्गठन पेयजल योजना (फेज-१) सम्मिलित हैं। ट्रेच-३ के अंतर्गत बांदा की मटौं नगर पंचायत पेयजल योजना व नरैनी नगर पंचायत पेयजल योजना, चित्रकूट की मानिकपुर नगर पंचायत पेयजल योजना, झांसी की टोडी फतेहपुर नगर पंचायत पेयजल योजना, हाथरस की हाथरस नगर पालिका परिषद सीमा विस्तार पेयजल योजना, फतेहपुर की खागा नगर पंचायत पेयजल योजना, सिद्धार्थनगर की बिस्कोहर नगर

पंचायत पुनर्गठन पेयजल योजना, बहराइच में मिहीपुरवा नगर पंचायत पेयजल योजना, गोण्डा में गोण्डा नगर पालिका परिषद पुनर्गठन पेयजल योजना, प्रयागराज में मऊआइमा नगर पंचायत पेयजल योजना, कासगंज में सिद्धपुरा नगर पंचायत पेयजल योजना, कासगंज में भरगैन नगर पंचायत पेयजल योजना, उन्नाव में ऊग नगर पंचायत में पेयजल योजना, मिर्जापुर में चुनार नगर पालिका परिषद पेयजल योजना, बाराबंकी की रामसनेहीघाट नगर पंचायत पेयजल योजना, दरियाबाद नगर पंचायत पेयजल योजना तथा टिकैतनगर नगर पंचायत पेयजल योजना शामिल हैं। ये परियोजनाएं राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को बढ़ाने तथा जनता की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास श्री पी.गुरुप्रसाद, सचिव नगर विकास श्री अनुज कुमार झा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

आईसीसी रैंकिंग: दीप्ति को पछाड़कर सदरलैंड बनीं टी२० फॉर्मेट की 'नंबर-१' महिला गेंदबाज

नई दिल्ली। भारत की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा को पछाड़कर अस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एनाबेल सदरलैंड आईसीसी महिला गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पायदान पर पहुंच गई हैं। इससे पहले सदरलैंड अगस्त २०२५ में भी शीर्ष पायदान पर पहुंची थीं। दीप्ति



शर्मा को एक पायदान का नुकसान हुआ है। वह दूसरे पायदान पर हैं, जबकि पाकिस्तान की सादिया इकबाल तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन और ल रेन बेल क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर बनी हुई हैं। इस लिस्ट में जर्जिया वेयरहेम, चार्ली डीन, वेस्टइंडीज और नाशारा संधु ने १-१ स्थान की छलांग लगाई हैं। ये खिलाड़ी क्रमशः सातवें, आठवें, नौवें और १०वें स्थान पर पहुंच गई हैं। इस लिस्ट में भारत की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर पांच स्थान नीचे खिसककर ११वें नंबर पर पहुंच गई हैं। भारत की लेफ्ट-आर्म स्पिनर श्री चरणी

पांच स्थान ऊपर चढ़कर ४७वें स्थान पर पहुंच गई हैं। श्रीलंका की कविशा दिलहारी एक स्थान ऊपर चढ़कर ३२वें स्थान पर और चमारी अथापथु तीन स्थान ऊपर चढ़कर ४८वें स्थान पर पहुंच गई। भारत की अरुंधति रेड्डी २१ स्थान ऊपर चढ़कर ४४वें स्थान पर पहुंच गई। बल्लेबाजों की लिस्ट देखें, तो भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर २ पायदान ऊपर चढ़कर १३वें स्थान पर पहुंच गई हैं। कौर ने विशाखापत्तनम में श्रीलंका के विरुद्ध नाबाद ६६ रन की पारी खेलकर 'प्लेयर ऑफ द मैच' पुरस्कार अपने नाम किया था। इसके बाद अगले दो मुकाबलों में २६ और ६ रन की पारी खेली। अब हरमनप्रीत के पास शीर्ष १० में पहुंचने का 'गोल्डन चांस' है। अमनजोत कौर सात स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त ७८वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि श्रीलंका की बल्लेबाज हसिनी परेरा और इमेशा दुलानी ने अर्धशतक लगाने के बाद लंबी छलांग लगाई है। हसिनी परेरा ४२ गेंदों में ६५ रन बनाने के बाद ३१ स्थान ऊपर चढ़कर ४०वें स्थान पर पहुंच गई, जबकि इमेशा दुलानी ३६ गेंदों में ५० रन बनाने के बाद ७७ स्थान ऊपर चढ़कर ८४वें स्थान पर पहुंच गई हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी: केएल राहुल का लगातार दूसरे मैच में नहीं चला बल्ला

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी घरेलू टीम कर्नाटक की तरफ से खेल रहे हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों के उलट राहुल का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में निराशाजनक रहा है। वह लगातार दो मैचों में रन बनाने में सफल नहीं हो पाए हैं। केएल राहुल ३ जनवरी को त्रिपुरा के खिलाफ खेलने उतरे थे। उस मैच में वह ३५ रन बना सके थे। इसके बाद ६ जनवरी को राजस्थान के खिलाफ राहुल मात्र २५ रन बनाकर आउट हो गए। राहुल का ये फॉर्म न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय है। राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुनी गई वनडे टीम का हिस्सा हैं। उन्हें विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है और उनका खेलना तय है। ऐसे में उनके बल्ले से रन नहीं निकलना भारतीय टीम के लिए चिंताजनक है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी वनडे सीरीज राहुल की कप्तानी में ही खेलेली थी। टीम इंडिया को इस सीरीज में २-१ से जीत मिली थी।



न्यूजीलैंड सीरीज में शुभमन गिल वापसी कर रहे हैं। ऐसे में राहुल बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में दिखेंगे और मध्यक्रम को मजबूती देने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर होगा। ३३ साल के राहुल ने अपने वनडे करियर की

शुरुआत जून २०१६ में जिम्बाब्वे के खिलाफ की थी। अब तक खेले ६१ वनडे की ८३ पारियों में १८ बार नाबाद रहते हुए ७ शतक और २० अर्धशतक की मदद से वे ३,२१८ रन बना चुके हैं। उनका औसत ४६.५० रहा है। पिछले १० वनडे मैचों में राहुल के प्रदर्शन पर गौर करें तो उनके बल्ले से दो अर्धशतक आए हैं। दक्षिण अफ्रीका सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में उन्होंने अर्धशतक लगाया था। पहले मैच में ५६ गेंद पर ६० तो दूसरे मैच में ४३ गेंद पर ६६ रन की पारी उनके बल्ले से आई थी। तीसरे मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था।

स्टीव स्मिथ ने संन्यास की संभावना को किया खारिज

नई दिल्ली। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के कार्यवाहक कप्तान की भूमिका निभा रहे स्टीव स्मिथ पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में किसी युवा को टीम की कमान सौंपने को तैयार हैं, लेकिन अपने संन्यास की किसी भी संभावना से उन्होंने इनकार किया है। सिडनी टेस्ट से पहले हुए प्रेस कन्फ्रेंस में स्टीव स्मिथ से उनके एशेज २०२७ में खेलने को लेकर सवाल पूछा गया। स्मिथ ने जवाब में कहा, "मैंने कुछ समय से कहा है, मैं इसे दिन-ब-दिन, सीरीज-दर-सीरीज देख रहा हूँ और हम देखेंगे कि चीजें कहां पहुंचती हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी ठीक कर रहा हूँ, मैं इसका मजा ले रहा हूँ, मैं अपना योगदान दे रहा हूँ, और मजा कर रहा हूँ। इसलिए मेरे लिए फिलहाल कोई आखिरी तारीख नहीं है। उन्होंने कहा, "हाल के कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए सकारात्मक परिणामों में

वृद्धि के कारण खेल हाल ही में अधिक मनोरंजक हो गया है। मुझे लगता है कि हमारे पास वाकई एक अच्छी टीम है। हम लगातार दो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेले हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिर्फ एक या दो लोग ही



काम पूरा कर रहे हों। खिलाड़ियों ने पूरे समय बहुत अच्छा काम किया है। इसी वजह से हम एक अच्छी टीम बने हैं। इस टीम का हिस्सा बनना अच्छा रहा है। अब एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर, मैं आने वाले कुछ खिलाड़ियों की मदद कर सकूंगा और उन्हें टेस्ट क्रिकेट का खेल सिखाने में मदद कर सकूंगा। स्मिथ ने सिडनी टेस्ट के बाद क्रिकेट से संन्यास ले रहे उस्मान

ख्वाजा पर कहा कि वह ख्वाजा की बैटिंग के मुरीद थे। मुझे याद है कि मैं न्यू साउथ वेल्स के लिए अंडर-१७ बनाम अंडर-१६ के कुछ गेम में उनके खिलाफ खेला था और उन्हें बैटिंग करते हुए देखा था। जिस तरह से उन्होंने बॉल को पुल किया, मुझे लगा, वो किसी से भी ज्यादा तेजी से लेंथ पकड़ता है। वे स्टंप के ऊपर से गेंद को पुल कर रहे थे। मुझे लगता है कि अपने पूरे करियर में, जब वह ऐसा कर रहा था, तब उन्होंने अपनी सबसे अच्छी बैटिंग की। अपनी कप्तानी में ख्वाजा को ड्रॉप किए जाने वाले सवाल पर स्मिथ ने कहा, "सबक न्टिनेट सीरीज में उन्हें ड्रॉप करना उनके लिए सबक की तरह था। पहले उन्हें स्पिन खेलने में समस्या होती थी, लेकिन ड्रॉप होने के बाद स्पिन खेलने पर उन्होंने काम किया और वह अब शायद स्पिन के हमारे सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं।

सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन स्टोक्स-लाबुशेन के बीच तीखी बहस

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे पांचवें मुकाबले के दूसरे दिन मैदान पर माहौल गर्मा गया। इस दौरान इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और अस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन के बीच तीखी बहस देखी गई। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन पांचवें एशेज टेस्ट के दूसरे दिन तीसरे सेशन के दौरान बहस में उलझ गए। इस दौरान इंग्लैंड के कप्तान ने लाबुशेन को कुछ तीखे शब्द कहे। ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड के कप्तान की गेंदों पर लगातार बाउंड्री लगाकर २६वां ओवर खत्म किया, जिसने स्टोक्स को गुस्सा दिला दिया था। जब स्टोक्स ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के पास से गुजरे, तो उन्होंने लाबुशेन से कुछ कहा और उनकी ओर इशारा किया, जिसके बाद टकराव बढ़ गया। इसके बाद स्टोक्स मुझे और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के पास गए। उन्होंने ट्रेविस हेड के कंधे पर हाथ रखा।

दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई। इस बीच अंपायर को दखल देना पड़ा। हालांकि दोनों खिलाड़ियों के बीच बातचीत पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूर्व कप्तान रिची

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पकड़ बना रखी है। इंग्लैंड ने पहली पारी में ३८४ रन बनाए। इस दौरान जो रूट ने १६० रन की पारी खेली, जबकि हैरी ब्रूक ने ८४ रन का



पॉटिंग का मानना है कि स्टोक्स ने लाबुशेन से कहा, "तीन बार, तीन बार तुमने मेरे साथ ऐसा किया है।" इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज लाबुशेन ने पलटकर जवाब दिया, जिसके बाद स्टोक्स उन्हें "चुप हो जाओ" कहते हुए भी नजर आए। सिडनी में खेले जा रहे मुकाबले के दूसरे दिन तक

योगदान टीम के खाते में दिया। मेजबान टीम के लिए माइकल नेसेर ने सर्वाधिक ४ विकेट निकाले। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने ३४.१ ओवरों के खेल तक २ विकेट गंवाकर १६६ रन बना लिए हैं। ट्रेविस हेड ६१ रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि मार्नस लाबुशेन ने ४८ रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

उधार के विवाद में व्यापारी पर चाकू से हमला

मऊ। जिले में उधार के विवाद में ३२ साल के नमकीन खाद्य सामग्री कारोबारी को चाकू गोद कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, चाकू करीब तीन घंटे तक उसके पेट में फंसा रहा। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब नौ बजे घोसी पुलिस थाना क्षेत्र के दरियाबाद गांव में हुई, जब उदयभान नाम के कारोबारी व्यापारी और एक ग्राहक के बीच उधार के पैसे चुकाने को लेकर बहस हो गई। पुलिस ने बताया कि विवाद बढ़ गया, जिसके बाद आरोपी ने कथित तौर पर उदयभान पर

चाकू से हमला किया, उसके कंधे और पेट पर वार किया, और उसे आग लगाने की भी कोशिश की। हमले के दौरान चाकू व्यापारी के पेट में फंसा गया। गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल व्यापारी को एम्बुलेंस से पहले एक रवास्थ केंद्र और बाद में मऊ के जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने एक मुश्किल अपरेशन के बाद चाकू निकाला। पुलिस ने बताया कि गंभीर हालत को देखते हुए उदयभान को आधी रात के आसपास बेहतर उपचार के लिए वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर

में भेज दिया गया। घोसी थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना पैसे के विवाद के कारण हुई। उन्होंने कहा, आरोपी पीड़ित को चाकू गोद कर भाग गया। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, और आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी का पता लगाने के लिए आस-पास के इलाकों में छापेमारी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि व्यापारी और लेनदारों के बीच बकाया पैसे को लेकर पहले भी विवाद हो चुके हैं।

विपक्ष को डर है कि VB-G RAM-G अधिनियम से उनके काले कारनामे उजागर हो जाएंगे: मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (VB&G RAM&G) अधिनियम के विरोध को लेकर भारत गुट की कड़ी आलोचना की और कहा कि अगर वे इस कानून का समर्थन करते हैं तो उनके पुराने कुकर्म उजागर हो जाएंगे। इस अधिनियम को एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक सुधार साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है क्योंकि जिन लोगों पर वर्षों से देश के संसाधनों को लूटने का आरोप है, वे अब बेनकाब होने से चिंतित हैं। मुख्यमंत्री योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री द्वारा संसद के हालिया शीतकालीन सत्र के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों के बारे में है... इस संबंध में एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किया गया है, जिसे वीबी-जी राम जी अधिनियम, २०२५ के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास परिदृश्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, गरीबों को भूखा मरने और युवाओं को पलायन करने और बेरोजगारी की पीड़ा झेलने के लिए मजबूर किया है, वे अब

चिंतित हैं कि यदि वे ऐसे सुधारों और ग्रामीण विकास के प्रति इस पारदर्शी दृष्टिकोण और विकसित भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, तो उनके कुकर्म उजागर हो जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वीबी जी राम-जी अधिनियम एक नए भारत की नींव होगा, और कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता



है जब राज्य विकसित हों, जो तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इसकी मूलभूत इकाई, गांव, विकसित हो। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा, तभी विकसित भारत का दृष्टिकोण आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि यह (VB&G RAM G अधिनियम) एक विकसित भारत की नींव रखेगा। एक विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित हों। राज्य तभी विकसित होंगे जब हमारी मूलभूत इकाई, गांव, विकसित होगी। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगे, जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे और जब श्रमिकों

को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित होगा, तभी एक विकसित भारत का सपना साकार होगा। मैं इसका स्वागत करता हूँ और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आश्चर्य व्यक्त किया कि वीबी जी राम जी अधिनियम का विरोध करने वाले इंडिया ब्लॉक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए था, जबकि वे अपने पुराने भ्रष्ट आचरणों का समर्थन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उनका इंडिया गठबंधन इस महत्वपूर्ण अधिनियम (वीबी जी राम जी अधिनियम) को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं। यह आश्चर्यजनक है कि देश, श्रमिकों, किसानों और गांवों के विकास के हित में उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम का समर्थन और स्वागत करने के बजाय, जिसके लिए इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री और एनडीए के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए था, वे खुलेआम अपने पुराने भ्रष्ट आचरणों का समर्थन कर रहे हैं। यदि हम वीबी जी राम जी अधिनियम की विशेषताओं को देखें, तो यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसे पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, गारंटी प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का निर्माण करने के लिए पारित किया गया है, जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी।

जेएनयू विवाद पर बोले मंत्री राजभर, विपक्ष का काम बस नारे लगाना, हंगामा करना है

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित नारेबाजी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल नारों, गीतों और शोर मचाने के माध्यम से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। राजभर ने कहा कि कुछ विपक्षी दल हैं उनका काम सरकार का विरोध करना है, वे कभी नारों से, कभी गीतों से और कभी शोर मचाकर ऐसा करते हैं। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा २०२० के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश से जुड़े एक मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज करने के फैसले के बाद आई है। हालांकि, कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उमर खालिद और शरजील इमाम अभियोजन और

सबूतों दोनों के लिहाज से गुणात्मक रूप से अलग स्थिति में हैं। राजभर ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) विधेयक, २०२५ की सराहना करते हुए इसे ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक लाभकारी पहल बताया। उन्होंने कहा, यह एक अच्छी पहल है, लोगों को १२५ दिनों का काम मिलेगा, और जिन भुगतानों का भुगतान नहीं हो रहा था, उन्हें ७ दिनों के भीतर देने की बात कही जा रही है। इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के नए वीबी-जी राम जी अधिनियम के विरोध में "एमजीएनआरईगा बचाओ" नाम से तीन चरणों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। ४५ दिनों के इस अभियान का पहला चरण, जिसे 'एमजीएनआरईगा बचाओ संग्राम' कहा जा रहा है, ८ जनवरी से शुरू होगा और इसमें सभी राज्य, जिले, ब्लॉक और ग्राम पंचायतें शामिल होंगी।



फैक्टरी की जर्जर दीवार गिरने से मलबे में एक मजदूर की मौत

फतेहपुर। जिले के मलवां थाना क्षेत्र के सौरा में मंगलवार को जल निकासी के लिए नाले की खुदाई करते समय एक फैक्टरी की जर्जर दीवार ढह जाने से उसके मलबे में पांच मजदूर दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। मलवां थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) राजकिशोर ने बताया कि मंगलवार को सौरा औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी के लिए जेसीबी मशीन से नाले की खुदाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान

बंद पड़ी शारदा स्टील फैक्टरी की जर्जर दीवार ढह गई जिसके मलबे में पांच मजदूर दब गए। उन्होंने बताया कि मलबे में दबने से लखीमपुर खीरी के मजदूर राजेंद्र (४५) की मौके पर मौत हो गई, जबकि सीतापुर जिले के कल्लू (१८), संदीप (३२), कुन्नु (२८) और कुलदीप (१८) का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने बताया कि नाले की खुदाई और निर्माण का काम लखनऊ की एक निर्माण कंपनी को मिला हुआ है।

कोटवा गांव के खेत में लगा

समरसेविल पंप खोल ले गये चोर।

गोला गोकर्णनाथ खीरी, थाना नीमगांव की पुलिस चौकी सिकन्द्राबाद क्षेत्र के कोटवा गांव निवासी उमाकान्त मिश्र पुत्र शिवराम मिश्र का हज्जनपुर रोड पर सिंचाई के लिए खेत में लगा समरसेविल पंप को बीती सोमवार की रात अज्ञात चोरों ने बोरिंग से निकालकर चोरी कर लिया है। समरसेविल पंप चोरी की जानकारी मंगलवार सुबह तब हुई जब खेतों की ओर गए उमाकान्त

ने बोरिंग के पास समरसेविल में पड़ी पाइपों व तार को खेत में पड़ा देखा। मौके पर ही ११२ पुलिस को फोन कर जानकारी दी, साथ ही थाना नीमगांव में तहरीर दी है। प्रबीर कुमार गौतम थानाध्यक्ष नीमगांव, ने बताया कि तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज कर अतिशीघ्र चोरों को पकड़ा जाएगा, मौके पर चौकी इंचार्ज सिकंदराबाद को जांच के लिये भेजा गया है।

कपरहा गांव में निर्वाचन नामावली

का प्रकाशन किया गया।

गोला गोकर्णनाथ खीरी। विगत एक माह चली एसआईआर(पत) प्रक्रिया के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर अंतिम सूची के प्रकाशन के क्रम में १३६ गोला विधानसभा क्षेत्र के गांव कपरहा में निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन मंगलवार सुबह १० बजे से प्राथमिक विद्यालय कपरहा में

किया गया। कपरहा गांव के भाग संख्या ३३५ में कुल मतदाताओं ७५६ में ४०८ पुरुष व ३५१ महिलाएं व भाग संख्या ३३६ में कुल मतदाताओं ६४२ में ३६८ पुरुष व २७४ महिलाएं हैं। बूथ स्थल पर बीएलओ प्रदीप कुमार व शमा परवीन ने आये ग्रामीणों को लिस्ट दिखाया।

मेडिकल व्यवसाई से दस हजार की नगदी व मोबाइल की लूट।

लखीमपुर खीरी। हैदराबाद थानाध्यक्ष क्षेत्र में गन प्वाइंट पर मेडिकल व्यवसाई से दस हजार की नगदी व मोबाइल की लूट। उससे पहले रोशननगर निवासी पत्रकार अविनाश वर्मा को भी किया लूटने का प्रयास। गोला गोकर्णनाथ खीरी। हैदराबाद थाना क्षेत्र के ममरी रोशननगर मार्ग पर सोमवार रात करीब ८ बजे बदमाशों ने एक मीडिया कर्मी अविनाश वर्मा को लूटने का प्रयास किया, उनके पीछे दूसरे बाइक सवार के साथ घटना को अंजाम दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोशननगर निवासी अविनाश चंद्र वर्मा गोला से अपने गांव रोशन नगर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने रोशननगर रोड पर बने नाले के

पास बदमाशों ने उनके ऊपर डंडे से प्रहार कर दिया, लेकिन बाइक की स्पीड तेज करके वह किसी तरह बच निकले। उनके पीछे बाइक से आ रहे से रोशन नगर निवासी मेडिकल व्यवसायी आशीष अग्निहोत्री से बदमाशों ने गन प्वाइंट पर रोक कर उनकी पर्स पर्स में रखे दस रुपये व सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल फोन लूट लिया। आशीष अग्निहोत्री ने बताया कि गोला से वापस घर आ रहे थे हो ममरी रोशननगर मार्ग पर नाहरिया पर शाम करीब ८ बजे ५ या ६ बदमाशों ने घटना का इल्जाम दिया यहाँ तक बताया कि डण्डे से प्रहार किया, ममरी से जीप आ रही की रोशनी देख कर बदमाश लूट कर भाग गए।

घटना की जानकारी हैदराबाद पुलिस को दी सूचना पर घटना स्थल का पुलिस ने मौका मुआयना किया। वही रोशननगर के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर पहले पुलिस सुरक्षा रहती थी, जो अब वह देखने को नहीं मिल रही पुलिस सहायता केंद्र भी था जो वह धराशाही कर दिया गया पुलिस सहायता केंद्र का नामो निशान हट गया, इससे वहाँ लोगो फिर लूट भय होने लगा, हैदराबाद एस ओ सुनील कुमार मलिक ने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए दो बीट सिपाहियों की गस्त लगती थी मेरे संज्ञान में नहीं है सुरक्षा के लिए यहाँ पर सिपाहियों को लगाया जायेगा।

हैदराबाद पुलिस ने शान्तिभंग मे दो लोगो को किया गिरफ्तार

गोला गोकर्णनाथ खीरी।थानाध्यक्ष थाना हैदराबाद सुनील मलिक के नेतृत्व में थाना हैदराबाद पुलिस टीम द्वारा दिनांक ०६.०१.२०२६ को शान्ति भंग करने वाले ०२ नफर अभि०गण,१. तेजपाल यादव पुत्र राजाराम यादव उम्र करीब ३० वर्ष

निवासी ग्राम मढिया सडक थाना हैदराबाद जिला खीरी व २. शेर सिंह पुत्र रामप्रसाद उम्र करीब ४५ वर्ष नि०ग्रा० नौगंवा थाना हैदराबाद खीरी को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा १७०६१२६६१३५ बीएनएसएस में विधिक कार्यवाही

हेतु मा० न्यायालय गोला के समक्ष भेजा गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अशोक कुमार सिंह, खेमन्द्र कुमार सिंह व आरक्षी राजू वर्मा, शिवेन्द्र कुमार थाना हैदराबाद प्रमुख रूप से सामिल रहे।

भाजपा पूरी तरह बेईमानी और भ्रष्टाचार पर उतर आई है : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूरी तरह बेईमानी और भ्रष्टाचार पर उतर आई है। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को लूट लिया है और जनता को धोखा देने के लिए अब मंत्रिमंडल विस्तार जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि २०२७ का विधानसभा चुनाव प्रदेश में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर पूरी ताकत से जुटना होगा। मंगलवार को समाजवादी पार्टी मुख्यालय में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने आम जनता का जीना दूभर कर दिया है। सरकार की विफलताओं के कारण जनता का भरोसा उससे उठ चुका है और

प्रदेश में अब परिवर्तन तय है। उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी, क्योंकि जनता का विश्वास सपा पर है और २०१२ से २०१७ के बीच



समाजवादी सरकार में हुआ विकास आज भी लोगों को याद है। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि

वे हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए पूरी सजगता और जिम्मेदारी के साथ काम करें तथा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाएं। उन्होंने कहा कि २०२७ में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की जाएगी। सभी वर्गों को सम्मान और न्याय मिलेगा तथा विकास को नई दिशा दी जाएगी। अखिलेश यादव ने घोषणा की कि समाजवादी सरकार बनने पर गोमती रिवरफ्रंट पर महाराजा बिजली पार्सी की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की जाएगी और सभी महापुरुषों का सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा ही समाज को सही दिशा में ले जा सकती है। समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है और इस संघर्ष में जनता पूरी मजबूती से पार्टी के साथ खड़ी है।

संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग लड़की और युवक के शव बरामद

एटा। जिले के एक गांव की १७ वर्षीय लड़की और १८ वर्षीय युवक के शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवक १२वीं का छात्र था, जबकि नाबालिग लड़की ११वीं कक्षा में पढ़ रही थी और दोनों मिरहची थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, युवक की हालत बिगड़ने पर उसके परिजन उसे पहले एटा के वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल

कॉलेज ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसने बताया कि कुछ समय बाद, लड़की को भी उसी मेडिकल कॉलेज लाया गया और डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि दोनों एक ही जगह के थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे, हालांकि उनके परिवार इस बारे में बोलने से बच रहे हैं। परिवार वाले बिना पोस्टमार्टम कराए शवों को घर ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन घटना की सूचना पुलिस को मिल गई। सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। सूत्रों

ने यह भी कहा कि दोनों के शव उनके संबंधित घरों में कथित तौर पर फंदे से लटके मिले थे और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक, क्षेत्राधिकारी (सदर) संकल्प दीप कुशवाहा ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साक्ष्य जुटाने के लिए फील्ड यूनिट और श्वान दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने कहा कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही चल पाएगा। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

राजधानी लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में गलन, शीतलहर और कोहरे की तिहरी मार

लखनऊ। राजधानी लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में गलन, शीतलहर और कोहरे की तिहरी मार से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है वहीं अधिसंख्य क्षेत्रों में हवा की सेहत भी खतरनाक स्थिति में पहुंच गयी है। मौसम विभाग के अनुसार गलन भरी ठंड और शीतलहर से राहत की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। इस दौरान कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने के आसार हैं। लखनऊ और कानपुर में मंगलवार दोपहर तक कोहरे और धुंध के चलते सूर्य देव के दर्शन नहीं हुये। सुबह ११ बजे तक दोनों ही महानगरों में अधिकतम तापमान १३ डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। कमोवेश यही हालात प्रयागराज, आगरा, इटावा, अलीगढ़, उन्नाव और बाराबंकी समेत तमाम शहरों में रहे। यहां अधिकतम तापमान १४-१५ डिग्री के करीब

दर्ज किया गया। इस दौरान वायु गुणवत्ता सूचकांक १४६ से १६४ के बीच रहा। बीती रात राज्य के अधिासंख्य क्षेत्रों में पारा ७-८ डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम के तलख तेवरों को देखते हुये राज्य सरकार के निर्देश पर कक्षा आठ तक के विद्यालयों को आठ जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं जबकि नौवीं से १२वीं तक की कक्षाओं के खुलने और बंद करने का समय बदला गया है। चिकित्सकों ने मार्निंग व कर्स को सुबह की सैर से परहेज करने की सलाह दी है। विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और सीने व हृदय के रोगियों को सूर्य निकलने के बाद ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गयी है। इस बीच कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग पर लंबी

दूरी की दर्जनों ट्रेन अपने निधिारित समय से १२ घंटे तक की देरी से चल रही हैं वहीं लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर कई उड़ाने विलंब से हैं। यमुना एक्सप्रेस वे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे समेत अन्य राजमार्गों पर वाहन रेंग रेंग कर चलते दिखायी पड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जालौन, देवरिया और गोरखपुर समेत कई जिलों के जिलाधिकारी और अन्य आला अधिकारी सड़क पर उतर कर अलाव और रैनबसेरों का निरीक्षण करते दिखायी दे रहे हैं। हालांकि अलाव की सीमित संख्या के चलते निराश्रित ठंड में ठिठुर रहे हैं वहीं सड़क पर आवारा जानवर भी ठंड से बेहाल हैं। कई स्वयंसेवी संस्थायें और जानवर प्रेमी बेजुबानों को ठंड से बचाने के लिये तरह तरह के उपाय कर रहे हैं।

झांसी के थाना सदर बाजार तथा हरदोई के थाना जीआरपी को आईएसओ प्रमाण-पत्र प्राप्त, पुलिस महानिदेशक ने दी बधाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में झांसी के थाना सदर बाजार तथा हरदोई के थाना जीआरपी को आईएसओ प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। यह प्रमाण-पत्र मानकीत प्रक्रियाओं, गुणवत्तापूर्ण सेवा-प्रदान, रिकॉर्ड प्रबंधन और जवाबदेही को सुदृढ़ करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक यह उपलब्धि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी मार्गदर्शन तथा पुलिसिंग में निरंतर सुधार के निर्देशों के प्रभावी अनुपालन का परिणाम है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के कुशल नेतृत्व, सतत म नितरिंग और गुणवत्ता आधारित कार्य संस्कृति के चलते प्रदेश के इन दोनों थानों को आईएसओ मान्यता प्राप्त हुई है। आईएसओ प्रमाणन का उद्देश्य पुलिस थानों में कार्यप्रणाली को पारदर्शी, समयबद्ध और जनहितैषी बनाना है। इसके अंतर्गत शिकायत निस्तारण, अभिलेख संधारण, सेवा वितरण, आंतरिक निगरानी और जवाबदेही जैसे प्रमुख पहलुओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्थित किया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार यह उपलब्धि मुख्यमंत्री के 'आधुनिक, नागरिक-केंद्रित एवं परिणाम-उन्मुख पुलिस व्यवस्था'

के लक्ष्य को धरातल पर उतारने की दिशा में एक ठोस कदम है। राजीव कृष्ण (पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश) द्वारा थाना सदर बाजार (झांसी) एवं थाना जीआरपी (हरदोई) की पूरी टीम को बधाई



दी गई। साथ ही यह अपेक्षा व्यक्त की गई कि भविष्य में भी इसी निष्ठा, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ आमजन की सेवा की जाएगी तथा यात्रियों एवं नागरिकों को सुरक्षित, भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवा उपलब्ध कराई जाती रहेगी। वहीं विभाग का कहना है कि आईएसओ प्रमाणन से प्राप्त अनुभवों को प्रदेश के अन्य थानों में भी लागू करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे, ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यसंस्कृति और सेवा स्तर को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। यह उपलब्धि न केवल संबंधित थानों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि प्रदेश में पुलिस सुधारों की दिशा में एक प्रेरक उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।

बहुमजिली इमारत में आग, फायरब्रिगेड ने पाया काबू

कानपुर। बासमंडी स्थित सोहन लाल कंपाउंड स्थित एक बहुमजिली इमारत की दूसरी मंजिल पर एक लेदर सैडरी गोदाम में भीषण आग लगी जिससे अफरातफरी मच गयी। घटना की गंभीरता को देखते हुए आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। घटना के दौरान बिल्डिंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सोमवार को प्रातरु ११ बजे सोहल लाल हाता में आग लगने की जानकारी फायरब्रिगेड को क्षेत्र के बिलाल द्वारा दी गई। सोहन लाल का हाता काफी घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इसलिए मुख्य अग्निशमन

अधिकारी दीपक शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे और लाटूश रोड, कर्नलंगज, फजलगंज, मीरपुर, जाजमऊ समेत कई फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंची तो देखा कि आसिफ अनवर पुत्र अनवारुल हक के लेदर सैडलरी गोदाम में शोले भड़क रहे थे। अनुमान है कि ये आग शार्ट सर्किट से लगी है। आसपास आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र होने के कारण फायर जवानों ने पहले आग को आगे बढ़ने से रोका। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लेकिन गोदाम को भारी नुकसान पहुंचा है।

मऊ में दादर एक्सप्रेस को बम से उड़ाने की धमकी, ट्रेन खाली कराकर की गई जांच

मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन पर सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अधिकारियों को गोरखपुर से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस जा रही ट्रेन संख्या १५०१८ में विस्फोटक उपकरण होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां घेहाई अलर्ट पर आ गईं और पूरे स्टेशन पर तनावपूर्ण माहौल छा गया। जानकारी के अनुसार, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए। पुलिस

अधीक्षक इलमारन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार पुलिस दल के साथ स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों के साथ मिलकर तुरंत ट्रेन को खाली कराया और यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलाकर ट्रेन की गहन जांच शुरू की गई। अधिकारियों के अनुसार, ट्रेन संख्या १५०१८ के प्रत्येक डिब्बे की गहन तलाशी ली जा रही है।

पत्रकारों की पेंशन व सुरक्षा पर विधायक राजेश्वर सिंह का आश्वासन, मीडिया सेंटर में हुआ संवाद

लखनऊ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की सामाजिक, आर्थिक एवं पेशेवर चुनौतियों को लेकर सरोजिनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने एक बार फिर संवेदनशील और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने का परिचय दिया। लाल बहादुर

क्रमवार विधायक के समक्ष रखा। पत्रकारों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए विधायक राजेश्वर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पत्रकार समाज की आवाज होते हैं और उनके हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

स्तर तक निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उनका यह आश्वासन पत्रकार समुदाय के लिए नई उम्मीद और विश्वास का संदेश लेकर आया। स्वागत समारोह के दौरान विधायक राजेश्वर सिंह को अंगवस्त्र पहनाकर, पुष्पगुच्छ एवं श्रीमद्भगवद्गीता भेंट कर सम्मानित किया गया। विधायक ने भी इस अवसर पर सरोजिनी नगर की विकासात्मक उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक "प्रगति की डगरें/सरोजिनी नगर" एवं डायरी पत्रकारों को वितरित की। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित पत्रकारों ने विधायक को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में पत्रकार पेंशन तथा पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। यह मुलाकात पत्रकार समुदाय के लिए न केवल संवाद का मंच बनी, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का शुभ संकेत भी साबित हुई। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश चंद मिश्रा, सुशील दुबे, अजय वर्मा, अजीत कुमार सिंह, रवि शंकर उपाध्याय, संजय धीमान, प्रदीप उपाध्याय, जेड. ए. सिद्दीकी, अविनाश राय, राजेश मिश्रा, अमन अग्रवाल, समीर (शाहनवाज), उमाकांत बाजपेई, शशिनाथ दुबे, त्रिनाथ शर्मा, अरुण शर्मा सहित अनेक पत्रकार उपस्थित रहे।



शास्त्री भवन एनेक्सी स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) के संयोजक प्रभात त्रिपाठी के आमंत्रण पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकारों ने विधायक राजेश्वर सिंह का गर्मजोशी एवं उत्साहपूर्वक स्वागत किया। स्वागत उपरांत संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने पत्रकारों से जुड़े वर्षों से लंबित मुद्दों/पत्रकार पेंशन व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा तथा पत्रकार सुरक्षा कानूनों को

उन्होंने आश्वासन दिया कि पत्रकार पेंशन के मुद्दे पर वह स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे और एक ठोस प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री पत्रकारों की भूमिका और योगदान को भली-भांति समझते हैं और इस दिशा में सकारात्मक निर्णय अवश्य लिया जाएगा। विधायक ने कहा कि पत्रकारों की समस्याएं केवल मांग नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती से सीधे तौर पर जुड़ा विषय हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि वह पत्रकारों के हर न्यायोचित मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर शासन

मिशन कर्मयोगी: सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग अनिवार्य सीएम योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 'मिशन कर्मयोगी' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी तंत्र को अधिक सक्षम, दक्ष और जनोन्मुखी बनाना है। मुख्यमंत्री ने 'मिशन कर्मयोगी' के तहत प्रदेश में अब तक हुई प्रगति और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें आईगोट (iGOT) कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। सीएम योगी ने कहा कि विभागों और सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और साइबर सिक्योरिटी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि अधिकारी एवं कर्मचारी बदलती तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को अपडेट कर सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी ट्रेनिंग सेंटरस कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े पाठ्यक्रम अवश्य तैयार करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सात दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किया जाए, जिससे कार्यकुशलता, निर्णय क्षमता और सेवा वितरण में और अधिक

सुधार हो सके। समीक्षा बैठक में बताया गया कि आईगोट कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। अब तक प्रदेश के 9.7 लाख से अधिक कार्मिक इस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं, जो वर्ष 2025 में देश भर में हुई कुल ऑनबोर्डिंग का लगभग 63 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि मिशन कर्मयोगी का वास्तविक लाभ शासन और आम जनता तक पहुंचे।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

संजय बाजपेई

सीतापुर

मो.9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

सुरेश नारायण मिश्र

क्षेत्रीय सम्पादक

सौरभ कुमार, बिहार

मो.09386075289

मो० अरशद

ब्यूरो चीफ

मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा साईं आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन

भातखण्डे संगीत

महाविद्यालय के पीछे,

कैसरबाग लखनऊ से

छपवाकर एमआईजी

2/379 रश्मिखंड

शारदानगर आशियाना

लखनऊ उ0प्र0 से

प्रकाशित।

आर.एन.आई

UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191.

9026560178

Email-

adbhutsamachar

@yahoo.in

adbhut_samachar

@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र

लखनऊ होगा।

सोहा अली खान ने पिता मंसूर अली खान पटौदी की याद में 'इंडन गार्डन्स' का किया दौरा

मुम्बई। क्रिकेट और बॉलीवुड की दुनिया में कुछ परिवार ऐसे रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और पहचान से अलग छाप छोड़ी है। इन्हीं में एक नाम है मंसूर अली खान पटौदी का, जिनकी विरासत आज भी चर्चा में रहती है। उनकी बेटी सोहा अली खान ने फिल्मों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई, जबकि मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। वह सिर्फ एक उम्दा क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय टीम के कप्तान भी रहे। उनके जन्मदिन पर, उनकी बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री सोहा अली खान ने कोलकाता के प्रसिद्ध स्टेडियम 'इंडन गार्डन्स' का दौरा किया। सोहा ने इस दौरे को वीडियो अपने सोशल मीडिया पर भी साझा किया। सोहा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह स्टेडियम में घूमती नजर आ रही है। उन्होंने पिता के

9608 के टेस्ट मैच की कुछ पुरानी झलकियां भी दिखाईं। इस मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत हासिल की थी और यह जीत उनके पिता की कप्तानी का यादगार उदाहरण बनी। वीडियो को पोस्ट करते हुए सोहा ने लिखा,



"मैं उस मैदान पर खड़ी होना चाहती थीं, जहां मेरे पिता ने खेला और कई बार भारत का नेतृत्व किया। भले ही स्टेडियम उस समय खाली था, लेकिन मेरे पिता की याद हमेशा यहां जिंदा रहती है। 9608 का वह टेस्ट मैच आज भी भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे

यादगार मैच माना जाता है। उन्होंने लिखा, "इस मैच में एंडी र बर्ट्स की एक गेंद से उनके चेहरे पर चोट लगी थी, उनके मुंह की हड्डी टूट गई, फिर भी उन्होंने मैदान छोड़ने के बजाय टीम का नेतृत्व किया और भारत को 25 रन से जीत दिलाई। इस मैच में उनके साहस और लगन की मिसाल आज भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। सोहा ने अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "स्टेडियम में मेरे पिता की याद हमेशा जिंदा रहेगी। मेरे लिए हमेशा एक महान क्रिकेटर अब्बा रहेंगे। मंसूर अली खान पटौदी ने 20 दिसंबर 9608 को प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर से शादी की थी। इस शादी से उनके तीन बच्चे हुए, बेटा सैफ अली खान और बेटियां सोहा और सबा। सैफ और सोहा ब लीवुड इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, जबकि उनकी छोटी बहन सबा ज्वेलरी डिजाइनिंग में करियर बना रही है।

फातिमा सना शेख ने पहली बार की क्लिफ जंपिंग

मुम्बई। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री फातिमा सना शेख, अपने करियर के साथ-साथ जिंदगी के छोटे-बड़े पलों का भी लुत्फ उठाती हैं। हाल ही में उन्होंने क्लिफ जंपिंग का अनुभव किया। इस शानदार अनुभव का वीडियो उन्होंने अपने आधिकारिक



इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इसमें वे एक ऊंची पहाड़ी से नदी में छलांग लगाती नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उन्होंने अपने अनुभव को शेयर करते हुए लिखा कि छलांग लगाने से पहले मुझे किनारे पर खड़े होकर हिम्मत जुटाने में पूरे 20 मिनट लग गए। आखिरकार मैंने फैसला किया और कूद गई। अभिनेत्री ने लिखा, "हवा में वह पल, जब पानी से टकराने से ठीक पहले का समय होता है, वह बहुत लंबा और डरावना लगता है। पेट में एक अजीब सी घबराहट होती है, डर भी लगता है और कुछ समझ में भी नहीं आता है, लेकिन उन कुछ सेकंड में मैंने महसूस किया कि डर धीरे-धीरे जोश में बदल रहा था।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक